संपादकीय जागरण

शनिवार, 14 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 2 वि. 2075

संकल्प लेकर पुरुषार्थ करने वाले की जीत निश्चित है

शर्मनाक जुमला

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के इस बेजा बयान पर हंगामा होना ही था कि अगर 2019 के आम चुनाव में भाजपा जीतती है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। हालांकि वह पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि भारत को हिंदू पाकिस्तान जैसा बनने से बचना चाहिए, लेकिन इस बार वह हद लांघकर यह कह गए कि भाजपा के फिर सत्ता में आने पर भारत की स्थिति वैसी ही होगी जैसी आज पाकिस्तान की है। चूंकि शशि थरूर इतिहास के साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के भी जानकार हैं और वह पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं इसलिए वह इससे अच्छी तरह अवगत होंगे कि इस देश की स्थिति और साथ ही उसकी छवि कैसी है? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई मान-सम्मान है और न ही स्थान। वह आतंकी संगठनों को पालने-पोसने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। समझना कठिन है कि शशि थरूर को भाजपा के प्रति अपना विरोध भाव दर्ज कराने के लिए हिंदू पाकिस्तान जैसा शर्मनाक जुमला ही क्यों ठीक लगा? निःसंदेह यह नहीं माना जा सकता कि वह इस जुमले को उछालने के नतीजों से अनजान रहे होंगे, क्योंकि वह अपने बयान की व्याख्या करने के साथ ही उसे उचित बताने में लगे हुए हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा बयान दिया। तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति खतरनाक ही नहीं, देश को बदनाम करने वाली भी है। उनका बयान महज सनसनीखेज ही नहीं है। यह देश और खासकर हिंदू समाज को नीचा दिखाने वाला भी है। खराब बात यह है कि वह अपने आपत्तिजनक बयान पर कायम रहने में ही अपना भला देख रहे हैं। शायद वह इससे भी अनभिज्ञ ही रहना चाहते हैं कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भगवा आतंकवाद का जुमला उछालकर पार्टी के समक्ष कैसी मुसीबत खड़ी की थी?

शशि थरूर महज एक नेता ही नहीं हैं। वह लेखक और विचारक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनसे यह बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था कि वह इतनी बेतुकी बात बोलेंगे। उन्होंने एक खराब और गैर जरूरी बयान दिया, इसकी पुष्टि इससे होती है कि खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। यह देखना दयनीय है कि बुद्धिजीवी नेता माने जाने वाले शशि थरूर ने खुद को मणिशंकर अय्यर और संजय निरूपम की पंक्ति में खड़ा कर लिया। हिंदुत्व के नाम पर उग्रता दिखाने और जब-तब कानून हाथ में लेने वालों की हरकतों पर शशि थरूर की चिंता समझ में आती है, लेकिन एक तो इन सबको भाजपा से नहीं जोड़ा जा सकता और दूसरे ऐसे तत्वों की गतिविधियां नई नहीं हैं। यह अवश्य है कि सोशल मीडिया के इस दौर में उनकी कथनी और करनी कहीं ज्यादा प्रचार पाती है। ऐसे तत्व सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी सक्रियता दर्ज कराने में भी सफल हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे भाजपा की मदद से भारत को पाकिस्तान जैसा बनाने में जुटे हुए हैं। यह अजीब है कि एक अर्से से खुद सोशल मीडिया में सक्रिय शशि थरूर उसके असर से अपरिचित दिखे।

वर्षाजल की चिंता

लगातार सूखते धरती की कोख को पानी से लबालब करने के लिए एक बार फिर प्रयास शुरू होने जा रहा है। 16 जुलाई से भूजल सप्ताह में जल प्रदूषण रोकने के भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अधिकतर शहरी क्षेत्रों में अविवेकपूर्ण अतिदोहन से प्रदेश के 217 ब्लाकों में भूजल स्तर गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है। इसे मान सभी रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास सिर्फ सरकारी स्तर पर दिख रहा है। जिनके कारण यह स्थिति हुई है, उनका इससे कोई जुड़ाव नजर नहीं आ रहा है। जिस संकट का कारण प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं, उसकी भरपाई वह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोग सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं, उनसे न तो क्षतिपूर्ति का कोई प्रयास हो रहा है और न ही इस अभियान से जोड़ने की कोई ठोस योजना दिख रही है।

> भूजल को लेकर यदि सरकार चिंतित है तो वह एक निश्चित आकार से बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य क्यों नहीं कर देती।

आशंका है कि हर बार की तरह कहीं इस बार भी भूजल सप्ताह रस्मअदायगी ही साबित न हो। भूजल को लेकर यदि सरकार चिंतित है तो वह एक निश्चित आकार से बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य क्यों नहीं कर देती। भवन निर्माण की अन्य शर्तों के साथ इसे भी क्यों नहीं जोड़ दिया जाता। बड़े सरकारी भवनों या स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग शत-प्रतिशत लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। ये कुछ ऐसे उपाय हैं, जिन्हें यदि अपना लिया जाए तो भूगर्भीय जल के लिए अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चिंताजनक बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत पोखर, तालाबों को शत-प्रतिशत अतिक्रमणमुक्त और जीवित करने के प्रयास भी नहीं हुए। पानी को लेकर मनुष्य हमेशा से ही जागरूक रहा है, इसलिए सरकार को इस सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान से आगामी चुनावों में कांग्रेस को नुकसान होगा?

आज का सवाल

क्या जम्मू-कश्मीर में अमन कायम करने के लिए राज्यपाल शासन जारी रखना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

शिक्षा और शिक्षकों की अनदेखी

जगमोहन सिंह राजपूत

जो देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता न देता हो और जो अपने अध्यापकों पर भरोसा न करता हो वह सुनहरे भविष्य की संकल्पना केवल सपनों में ही कर सकता है

लगभग 30 वर्ष पहले भोपाल से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षु अध्यापक एक गांव की हालत समझने के लिए वहां गए। वे मूलतः यह जानने के लिए वहां गए थे कि गांव में किन मूलभूत सुधारों की त्वरित आवश्यकता है और वहां चल रही विभिन्न योजनाओं को कैसे गति दी जा सकती है? जब वे सब गांव पहुंचे तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वह बुखार की गोली मांग रही थी। गांव में प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र तो था मगर वह चलता नहीं था। चूंकि संयोगवश प्रारंभिक चिकित्सा से परिचय और उपयोग का प्रावधान इन प्रशिक्षु अध्यापकों के प्रशिक्षण का भाग था इसलिए वे उस बूढ़ी महिला को बुखार की गोली दे सके। इस प्रसंग के बाद सभी का ध्यान मूलभूत आवश्यकताओं पर केंद्रित हो गया। इसे लेकर जो सार्थक चर्चा शुरू हुई उसमें से निकले अनेक बिंदु पिछले तीन दशकों से मेरा मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। उक्त घटना का प्रभाव प्रशिक्षु अध्यापकों पर भी पड़ा। निराशा तब होती है जब आज भी स्थिति में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। समझना कठिन है कि सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए ईमानदारी एवं कर्मठता से प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? हर परिवार को सर्वाधिक प्रिय तो बच्चे ही होते हैं। पूरा परिवार उनके भविष्य निर्माण के लिए परिश्रम करता है और उनकी चिंता करने के क्रम में सबसे पहले अच्छे स्कूल की ओर देखता है। आज देश के 65 फीसद लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 40-50 साल पहले वे खुशी-खुशी भेजते थे। अब मजबूरी में भेजते हैं, क्योंकि वे यह देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही अच्छी मानी जाती है और वह केवल अधिक फीस देने वाले स्कूलों में ही उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की फीस देना अधिकांश परिवारों के लिए संभव नहीं है। बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण आवश्यक है और इसे अब सभी अच्छी तरह समझते भी हैं। दुर्भाग्य से आज भी सरकारी तंत्र स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जनमानस में अपनी साख बना नहीं पाया है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने के कारण मेरा यह मानना है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार केवल नई योजनाओं अथवा सरकारी अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर संभव नहीं है। कुछ बड़े साहसिक निर्णयों की आवश्यकता है। सबसे पहले प्राचीन भारत की परंपरा के तहत विद्या प्राप्ति के चार तत्वों को समझाना चाहिए। ये चार तत्व हैं- अध्ययन, मनन, चिंतन और उपयोग। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जिसके उपयोग के संबंध में सिखाने वाला ही अनभिज्ञ हो। इसी तरह उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है जो व्यक्ति की मनन और चिंतन शक्ति को प्रखरता न प्रदान करे। जिस शोध एवं नवाचार में सर्वजन कल्याण का लक्ष्य निहित न हो वह केवल लाभांश कमाने के लिए उठाया गया कदम बन कर रह जाता है। सर्वभूत हिते रतः की परंपरा वाली प्राचीन भारत की संस्कृति से अपरिचित व्यक्ति ही केवल अपने संबंध में सोचेगा। नदियों के किनारे उद्योग लगाकर उन्हें लगातार प्रदूषित कर रहे लोग भ्रष्ट व्यवस्था को धन देकर पर्यावरण नियमों के पालन का प्रमाणपत्र भले ही ले लें वे आने वाली पीढ़ियों के प्रति अन्याय कर रहे होते हैं। इनमें उनकी अपनी पीढ़ियां भी शामिल होती हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर नई पीढ़ी को शिक्षा प्राप्ति के दौरान प्राचीन भारतीय संस्कृति से अपरिचित रखने से बाज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रत्येक देश शिक्षा में गतिशीलता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। वह नए को स्वीकार करता है मगर अपनी संस्कृति से संबंध भी बनाए रखता है। भारत में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को लागू करने का सपना देखने के स्थान पर हमें चीन के व्यावहारिकता से भरे क्रियान्वयन से सबक लेना चाहिए, जहां स्कूली शिक्षा में समुदाय और सरकार, दोनों की भागीदारी तय है।

अवधेश राजपूत

प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना सरकारों का उत्तरदायित्व है मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि समाज इसकी सफलता की चिंता न करे। यह एक तथ्य है कि अपने देश में सामाजिक सहयोग के अभाव में अनेक प्रयास असफल हो गए हैं। पंचायतों को अध्यापक नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। अधिकांश नियुक्तियां पक्षपात और भ्रष्टाचार की कहानी कह रही हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आम लोगों ने अपना सामाजिक और सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं निभाया। यदि कोई राज्य सरकार किसी विभाग में 22 हजार सरकारी नियुक्तियों में से 18 हजार पर एक ही जाति के लोगों को नियुक्त करे तो इसका असर सब पर पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम देश के भविष्य पर भी पड़ेगा। जब राज्यों के लोक सवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को न्यायपालिका कई बार निरस्त करे तो युवा पीढ़ी का व्यवस्था पर विश्वास डगमगाता है और चारों ओर निराशा-हताशा फैलती है।

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों की गिरती साख के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है मगर यह भुला दिया जाता है कि वे किन कठिन परिस्थितियों में कार्य करते है? यदि जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए एक तय राशि लेने के लिए ही जाने जाते हों तो सरकारी स्कूलों में सुधार कैसे संभव होंगे? हाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने व्यवहार से यह स्पष्ट किया कि इस देश में राजनेता अध्यापकों का कितना सम्मान करते हैं? उन्होंने उन सबका प्रतिनिधित्व किया जो महिलाओं का असम्मान करने में हिचकते नहीं। यदि ऐसी घटना फिनलैंड या नार्वे जैसे किसी देश में होती तो 24 घंटे के अंदर नेताश्री अपने घर चले गए होते और उनका नाम राजनीति में सुनाई नहीं देता। आखिर उस मुख्य सचिव का क्या जिसने अध्यापिका को मुअत्तल कर दिया? नौकरशाहों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों का पालन करेंगे और जहां भी उन्हें नियमों के विरुद्ध जाने को कहा जाएगा वे कम से कम अपनी राय फाइल पर स्पष्ट लिखें।

अब किसी को ऐसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि जिला या ब्लाक स्तर पर अध्यापकों से कैसा व्यवहार किया जाता है? सुधार संभव है यदि नेता और नौकरशाह अपने कर्तव्य ढंग से निभाएं। यदि किसी क्षेत्र के विधायक और सांसद अपनी जन निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हों और वे शिक्षा सुधार में रुचि लेते हों तो सरकारी अधिकारी कोई दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। संवेदनहीन नौकरशाहों और नेताओं के कारण कई अध्यापक 25-25 वर्ष तक दुर्गम क्षेत्र में रहने को मजबूर हैं। इसके विपरीत कितने ही रसूख वाले अपना लगभग सारा सेवाकाल राजधानी या बडे शहरों में ही संपन्न कर लेते हैं। यदि केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में नियमानुसार तय अवधि के बाद स्थानांतरण हो सकते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? जो देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता न देता हो और जो अपने अध्यापकों पर भरोसा न करता हो वह सुनहरे भविष्य की संकल्पना केवल सपनों में ही कर सकता है।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

जोखिम भरी तीर्थ यात्राएं

तरुण विजय

भारत सरकार को चीन की भांति नेपाल से भी कैलास-यात्री व्यवस्था को संस्थागत रूप देना चाहिए

हिंदू धर्मप्राण लोग सदियों से अपनी जान जोखिम में डालकर तीर्थ यात्राएं करते आ रहे हैं। जिन तीर्थ यात्राओं पर जाने से पहले अनेक यात्री अपना तर्पण भी कर जाते थे और गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से नमन कर विदा देते थे उनमें कैलास मानसरोवर यात्रा, बलूचिस्तान में माता हिंगलाज यात्रा प्रमुख है। आधुनिक समय की तीर्थयात्रा अमरनाथ को भी इसी श्रेणी में मान सकते हैं। अमरनाथ यात्रा जिहादी आतंकवाद की धमकियों, अन्य अवरोधों और मौसम बिगड़ने से अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा के बावजूद बेरोकटोक चलती रही है। 2000, 2001, 2002, 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा आदि आतंकी संगठनों के कायर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमले किए और कई तीर्थयात्रियों को मार डाला। फिर भी न यात्री कम हुए, न यात्रा थमी। 12756 फीट की हड्डियां कंपा देने वाली बर्फानी कठिनाइयों को पार कर छह लाख से ज्यादा हिंदू तीर्थयात्री हर साल अमरनाथ जी जाते हैं-सरकार सुविधाएं दें तो भी ठीक, न दे तो भी अपनी व्यवस्था स्वयंकर भोले बाबा का नाम जपते हुए शांति पूर्वक यात्रा कर आते हैं। यात्रा में जान जाए तो जाए, लेकिन शिव दर्शन की तड़प उन्हें आगे बढ़ाती रहती है।

बलूचिस्तान में माता हिंगलाज 52 शक्ति पीठों में से एक है। रेगिस्तान के अपार विस्तार से गुजरते हुए हिंगोल नदी के किनारे माता का शक्तिपीठ पुराणों में भी सर्वाधिक कठिन यात्रा का धाम माना जाता था। यात्री प्यास, थकान और गर्मी से प्राण त्याग देते थे। अब सड़क बनने से यात्रा कुछ सुगम तो हुई है, लेकिन जिहादी आतंक का खतरा बना रहता है। कैलास मानसरोवर इन सभी यात्राओं में विशिष्ट, अतुलनीय, अनुपमेय यात्रा है। यह इतनी कठिन है कि इसे दूसरा जन्म लेने के समान माना गया है। इसी कारण मराठी भाषा में तो स्वर्गीय का समानार्थी शब्द ही 'कैलास वासी' होना बन गया। महाभारत में भी कैलास मानसरोवर का उल्लेख है। भारतीय मानस, साहित्य, संस्कृति-मूलक ग्रंथों में मानसरोवर अलंकारों, उपमाओं और श्रद्धा के शिखर पर विद्यमान है। यहां शिव परिवार का साक्षात निवास है। मान्यता है कि देवगण मानसरोवर में स्नान के लिए आते हैं। यह सनातन वैदिक परंपरा, जैन और बौद्ध सभी के लिए समान श्रद्धा का स्थान है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव की निर्वाणस्थली यहीं है। बौद्ध यहां निर्वाण का मार्ग मानते हैं। तिब्बती बौद्ध 14 से 18 हजार फीट की ऊंचाई के इस क्षेत्र की दंडवत परिक्रमा करते हैं। इसमें तीन से पांच सप्ताह लगते हैं। प्रसिद्ध तांत्रिक योगी मिला रेपा की गुफा भी कैलास पर्वत के मार्ग में है। संसार के इतिहास में संभवतः कैलास पर्वत ही ऐसा है जहां धार्मिक आस्था के सम्मानार्थ किसी को पर्वतारोहण की अनुमति कभी भी नहीं दी गई।

यह क्षेत्र संसार की महान नदियों सतलज, झेलम, सिंधु, मीकांग और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है। स्वामी प्रणवानंद, जो वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ने 21 बार कैलास यात्रा की थी। उन्होंने यह भी सिद्ध किया था कि गंगा का मूल स्रोत भी कैलास-मानसरोवर में है और मानसरोवर तल से एक अंतर्धारा गोमुख तक पहुंचती है। पहले भारत से कैलास-मानसरोवर यात्रा के लिए दस से अधिक मार्ग थे। मुंश्यारी-मिलम ग्लेशियर (उत्तराखंड) से गांधी जी की अस्थियां मानसरोवर में विसर्जन के लिए भेजी गई थीं। माणा (बद्रीनाथ) होते हुए पांडवों के स्वर्गारोहण के मार्ग माने जाने वाले वसुधारा से भी मानसरोवर का मार्ग था। हिमाचल में शिपकी ला और लद्दाख में देमछोक से भी यात्री जाते थे। अब भारत और चीन सरकार केवल उत्तराखंड के धारचूला-लिपू-लेख मार्ग और नाथू ला (सिक्किम) मार्ग से संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत यात्रा का आयोजन करते हैं। पहला मार्ग 1962 के चीनी आक्रमण के बाद बंद था, जो अटल बिहारी वाजपेयी और सुब्रमण्यम स्वामी के प्रयास से 1981 में खुला। नाथू ला का मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के सहयोग से 2015 में खुला, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यात्री नेपाल होते हुए भी कैलास मान सरोवर जाते हैं। वहां से निजी पर्यटन एजेंसियां चीनी वीजा एवं तिब्बत प्रवास की व्यवस्था कराती हैं।

हाल में भारी वर्षा के कारण करीब 1500 यात्रियों को नेपाल-भारत के संयुक्त अभियान में सुरक्षित निकालना पड़ा। दो यात्रियों की मृत्यु भी हुई। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि चीन की भांति नेपाल से भी भारत सरकार कैलास-यात्री व्यवस्था को संस्थागत रूप दे। जब दुबई, इराक जाने वाले भारतीयों को विदेश मंत्रालय समीक्षा, निरीक्षण आदि का कवच देता है तो नेपाल के साथ भी पर्यटन एजेंसियों का मानक निर्धारित करने और यात्रियों के हितार्थ संयुक्त व्यवस्था बनाने में समस्या नहीं आनी चाहिए। ध्यान रहे प्राण हथेली पर रखकर शिव दर्शन को जाने वाले तीर्थ यात्री भारत की सांस्कृतिक एकता के महान संरक्षक भी हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए यथासंभव उपयुक्त किए ही जाने चाहिए।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | विभिन्न देशों की औसत आयु

स्रोत : डेलॉयट, संयुक्त राष्ट्र

ऊर्जा

आत्मविश्वास

किसी कार्य को करने में हम किस स्तर तक सफल होंगे, इसका आभास हमें शुरुआत में ही हो जाता है। ऐसा हमारे आत्मविश्वास के कारण होता है। यदि कार्य शुरू करते वक्त हमारे अंतर्मन से यह आवाज आती है कि हम इसे कर सकते हैं तो निश्वित तौर पर उस कार्य को करने में हम काफी हद तक सफल रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम शुरुआत में यह मानने लगे कि यह कार्य हमसे नहीं होगा तो हो सकता है कि हम वह कार्य शुरू ही न कर पाएं। आत्मविश्वास का मतलब अपने स्वयं पर विश्वास करना है यानी यदि हमें अपने ऊपर यकीन है तो कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन जब हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता तो सारे कार्य हमें असंभव लगते हैं। दरअसल जब हम आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें मिली असफलता भी हमें दुख नहीं देती, क्योंकि कार्य को करने की खुशी उसी क्षण मिल जाती है और वही उसका इनाम है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कभी स्वयं पर से विश्वास मत खोइए। आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से समाज और दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं बौनी हो जाती हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर समस्या व संघर्ष को चुनौती के रूप में लेता है।

कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें उसके द्वारा अर्जित छोटी-छोटी उपलब्धियों पर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है तो भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर देता है। प्रशंसा एक उपहार है, जिसका परिणाम सदैव आनंदमय होता है। पशुओं तक को सर्कस के लिए अभ्यास करवाते समय रिंग मास्टर जब जरा-सा अच्छा करने पर उनको थपथपाता है तो वे भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि दर्शक तालियां बचाने से खुद को रोक नहीं पाते। वैसे कई बार आत्मविश्वास इंसान पर हावी होकर अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। आत्मविश्वास में व्यक्ति नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जबकि अभिमानी व्यक्ति एक दायरे में सिमटकर रह जाता है।

शंभूनाथ पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

विपक्षी एका अभी दूर की कौड़ी

अंशुमान राव का लेख 'विपक्षी एका की मजबूत होती बुनियाद' से यह तनिक भी आभास नहीं होता कि मोदी विरोधी दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों को तिलांजलि देकर किसी योग्य और सक्षम नेतृत्व के साथ एक दल के रूप में एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। लेखक ने इस विपक्षी एका की तस्वीर बनाने की कोशिश में राजग से दूर हो चुके चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके पीछे झलकते निहित राजनीतिक स्वार्थ की सर्वथा अनदेखी की गई है। भाजपा के लिए अपने सहयोगी दल के स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के बजाय राष्ट्र का हित प्रमुख है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर सबका साथ-सबका विकास की नीति के साथ केंद्र सरकार किसी राज्य विशेष को विशिष्टता प्रदान करने की अपेक्षा संपूर्ण भारत के स्थाई विकास के लिए कृतसंकल्पित है। कांग्रेस के 60 वर्षीय शासन में महज विकासशील बने रहने वाले भारत को अब विकसित राष्ट्र बनाना राजग सरकार की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ध्येयनिष्ठा को पराभूत करने के लिए विपक्षी एका का जो काल्पनिक चित्र खिंचा जा रहा है, उसके लिए विपक्षी दलों को निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहितैषी मुद्दों के साथ एक दल के रूप में खड़ा होना होगा, जो फिलहाल दूर की कौड़ी है। क्योंकि आज विपक्षी राजनीतिक दलों में से कोई भी दल अपनी दलीय निष्ठा को त्यागकर राष्ट्रहित में स्वयं को एक दल में विलीन करने के लिए तत्पर नहीं दिखायी देता, फिर भला विपक्षी एकता की यह बुनियाद कैसे मजबूत होगी?

pandeyvp1960@gmail.com

फ्रांस से आगे भारत

अर्थ व्यवस्था के मामले में भारत को आगे बताया गया है। इस मामले में भारत ने दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि भारत फ्रांस से आगे निकल गया है और भारत के लागों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार हो गया है। आज भी भारत के लोगों का जीवन स्तर फ्रांस के लोगों से काफी नीचे है। कारोबार में आगे बढ़ने का कारण यहां की सवा अरब आबादी है, न कि यहां की संपन्नता। फ्रांस की अपेक्षा भारत में अभी बहुत गरीबी है।

सार्थक, गाजियाबाद

जनता का आकलन

आम चुनाव और उपचुनाव के नतीजों को मतदाताओं द्वारा भांपने का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। यही कारण है कि जो भाजपा के मतदाताओं ने गत उपचुनावों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, और भाजपा को इसमें बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इसे मोदी के शासन काल में वादों के अनुरूप कार्य न कर पाने के कारण विफलता को माना जाना कतई उचित नहीं। सोचने की बात है कि इतने कामों को चार साल में पूरा कर पाना कोई सरल कार्य नहीं। इसके बावजूद केंद्र सरकार के कई कामों को जनता की सराहना मिली है।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

कूड़े की समस्या

दिल्ली में कूड़े की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है। कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि अधिकारों के लिए तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन राजधानी में कूड़े की इतनी बड़ी समस्या को हल करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है। कूड़ा निस्तारण की जो योजनाएं बनती हैं, उनको भी कार्यरूप नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि जगह-जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

पिंकी, लक्ष्मीनगर, दिल्ली

जल संचयन जरूरी

दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि बारिश के समय लोगों का जीना दूभर हो जाता है। हर साल नगर पालिकाएं नालों की सफाई का दावा करती हैं, लेकिन बारिश होते ही उनके दावों की पोल खुल जाती है। राजधानी में पेयजल का इतना संकट है, इसके बावजूद बारिश के दिनों में पानी के संचयन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बारिश का तमाम पानी ऐसे ही बह जाता है। बारिश के पानी के संचयन की व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए।

नीरज झा, दिल्ली विवि

आपराधिक कृत्य

भारतीय महिला क्रिकेटर मनप्रीत कौर को फर्जी डिग्री होने के बावजूद डीएसपी बनाया जाना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है? ऐसी डिग्री हासिल करना या बनाना दोनों आपराधिक कृत्य है। पंजाब सरकार को इस पहलू पर एक बार विचार करना चाहिए। पंजाब में बहुत गरीब और असली डिग्री वाले हैं, रोजगार देना है तो पहले उन्हें देना चाहिए।

मीना, दिल्ली

थरूर का बयान अशोभनीय

कांग्रेस नेता शशि थरूर के हिन्दू पाकिस्तान जैसे विचार ठीक नहीं हैं। आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी, तब न हिन्दू की बात थी न मुसलमान की। ये सब बाते आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान-हिन्दुस्तान बनने से उभरी, जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हमारा एक वृहद भारत होता तो आज कुछ और ही बात होती, परंतु नेताओं के स्वार्थ के कारण ये सब हुआ। हिन्दू पाकिस्तान कहना किसी भी दृष्टि से शोभनीय नहीं है।

mahesh_nenava@yahoo.com

ट्वीट-ट्वीट

हिमा दास ने हमें केवल एक मेडल भर नहीं दिया। उन्होंने अपने पदचिन्हों से न केवल ट्रैक में चमक बिखेर दी, बल्कि देश की चेतना भी जगा दी।

गौतम गंभीर@GautamGambhir

हिमा दास इतिहास रच रहीं हैं पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हालत देखिए, हिमा की अंग्रेजी पर टिप्पणी कर रहा है। हिमा की अंग्रेजी नहीं, ट्रैक पर उनकी रफ्तार देखिए।

दिबांग@dibang

हिमा दास की उपलब्धि के असर को ऐसे समझिए कि भारत के किसी भी सीनियर या जूनियर धावक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल नहीं जीता। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। सीना गर्व से चौड़ा हो गया।

राहुल बोस@RahulBose1

एक और बिटिया ने देश का नाम रौशन किया। पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में भारत की बेटियों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमत्कार किया है। गर्व है तुम पर हिमा।

मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

हिमा तुम लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा हो। तुमने कुछ विशेष कर दिखाया। बहुत-बहुत बधाई।

रवि शास्त्री@RaviShastriOfc

जनपथ

सुनवाई पर ताज को जज साहब तैयार,
उधर राम जी हैं पड़े तंबू में लाचार।
तंबू में लाचार फैसला उन पर लाओ,
देख रहा है देश दुआएं सबकी पाओ।
लटके सत्तर साल न अब लटकाओ भाई,
इस मसले की आप करो पहले सुनवाई।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 360**